गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 026
दि. 26.05.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तेल की मार से कराहता देश, पेट्रोल-डीजल के शतक ने बढ़ाई महंगाई की आग

पेट्रोल-डीजल ही नहीं LPG-CNG भी हो चुकी महंगी

नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। 11 दिन में लगातार चौथी बार दाम बढ़ने के बाद कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल भी तेजी से 100 रुपए के करीब पहुंच रहा है। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। 15 मई से अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। इससे ट्रांसपोर्ट, रोजमर्रा के सामान और घरेलू बजट पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.76 और पश्चिम बंगाल में 114.20 पर पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 117.35 वहीं, असम में 106.21, मध्य प्रदेश में 115.77,बिहार में 114.79, राजस्थान में 113.93 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 113.05, दिल्ली में 102.11, छत्तीसगढ़ में 109.59, गुजरात में 102.92, हरियाणा में 103.57, हिमाचल प्रदेश में 101.64 और जम्मू और कश्मीर में 108.47 प्रति लीटर हो गई है। झारखंड में 1 लीटर पेट्रोल का दाम आज से 107.02, केरल में 114.31, मणिपुर में 114.76, मिजोरम में 104.74,ओडिशा में 110.30, पंजाब में 105.90, सिक्किम में 109.88 हो गया है। वहीं, तेलंगाना में 116.78, त्रिपुरा में 104.89, उत्तराखंड में 100.96 एक लीटर पेट्रोल का दाम अब इस रेट पर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए से बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 92.49 रुपए से बढ़कर 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए और डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर हो गया।

15 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है, जिससे महंगाई के और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। देश के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल अब 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 102.76 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसकी कीमत 114.20 रुपये हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 117.35 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है, जो देश के सबसे महंगे राज्यों में शामिल है। बिहार में पेट्रोल 114.79 रुपये, मध्य प्रदेश में 115.77 रुपये, राजस्थान में 113.93 रुपये, महाराष्ट्र में 113.05 रुपये और तेलंगाना में 116.78 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड समेत लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये से बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 92.49 रुपये से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। चेन्नई में भी पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सभी की चिंता बढ़ा दी है।

ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर अब केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहा। घरेलू रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मई के मध्य से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि सीएनजी 4 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से फल-सब्जियां, दूध, अनाज, निर्माण सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ने की संभावना है, जिससे आम जनता का मासिक बजट और बिगड़ सकता है।

सरकार ने पहले कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दी गई थी। इसके बाद कुछ समय तक कीमतों में स्थिरता बनी रही। केंद्र सरकार के अनुसार पहले पेट्रोल पर कुल 21.90 रुपये और डीजल पर 17.8 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूला जाता था, जिसे घटाकर क्रमशः 11.90 और 7.8 रुपये किया गया। सरकार का दावा है कि इसी फैसले के कारण ईंधन की कीमतों में पहले बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हालांकि विपक्ष ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 8 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ईरान युद्ध और अंतरराष्ट्रीय हालात का हवाला देकर लोगों को गुमराह कर रही है। सपकाल ने कहा कि यदि सरकार महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने ईंधन मूल्य वृद्धि के विरोध में 26 मई से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है।

कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन तब भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा गया था। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार कम अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद जनता को महंगा ईंधन बेच रही है और तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद Supriya Sule ने भी देश की आर्थिक स्थिति और ईंधन संकट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के अलग-अलग मंत्रियों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, जिससे जनता भ्रमित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई मंत्री कहता है कि यूरिया की कमी होगी, कोई कहता है कि पेट्रोल-डीजल की सप्लाई सीमित है, जबकि दूसरी ओर सरकार दावा करती है कि स्थिति नियंत्रण में है। सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह पिछले छह महीनों से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने लोगों से पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फडणवीस ने बताया कि भविष्य में ईंधन की कमी की आशंका के कारण अचानक मांग में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन जमा न करें। लगातार बढ़ती महंगाई, ईंधन संकट और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देशभर में जनता अब इस उम्मीद में है कि सरकार जल्द कोई ऐसा समाधान निकाले जिससे पेट्रोल-डीजल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सके और राहत मिल सके।

घाटी में आतंक की नई साजिश, हिजबुल को सहारा देने उतरा जैश-उल-मुजाहिदीन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर और शोपियां जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी का दावा है कि घाटी में प्रतिबंधित संगठनों और अलगाववादी नेटवर्क के जरिए एक नया आतंकी तंत्र सक्रिय किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को आर्थिक और वैचारिक समर्थन देना था। एनआईए की जांच में अब एक नए संगठन "जैश-उल-मुजाहिदीन" का नाम सामने आया है, जिस पर आरोप है कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन Hizbul Mujahideen को समर्थन देने, धन जुटाने और घाटी में आतंकवाद को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित Jamaat-e-Islami (जेईआई) से जुड़े नेटवर्क की गतिविधियों की जांच के तहत की गई। एजेंसी को लंबे समय से इस बात की सूचना मिल रही थी कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की आड़ में कुछ संगठित समूह घाटी में अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी इनपुट के आधार पर एनआईए ने श्रीनगर और शोपियां में कई संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

जांच एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में वित्तीय दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। एजेंसी को संदेह है कि इन दस्तावेजों और उपकरणों का संबंध जम्मू-कश्मीर में सक्रिय उन नेटवर्कों से है, जो प्रतिबंधित संगठनों और उनके ट्रस्टों के माध्यम से धन के लेनदेन में शामिल थे। एनआईए अब इन दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धन कहां से आया, किसके माध्यम से भेजा गया और उसका उपयोग किन गतिविधियों में किया गया।

एनआईए की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि कथित नेटवर्क स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी गतिविधियों के नाम पर देश और विदेश से चंदा और आर्थिक सहायता जुटा रहा था। एजेंसी का आरोप है कि लोगों की भावनाओं और सामाजिक भरोसे का इस्तेमाल कर धन इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों में किया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए जुटाई गई रकम का एक हिस्सा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जा रहा था, जिससे घाटी में आतंकवादी ढांचे को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी।

एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि "जैश-उल-मुजाहिदीन" नामक संगठन की गतिविधियां हाल के महीनों में एजेंसियों की नजर में आई थीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह संगठन घाटी में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने, अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने और आतंकी संगठनों के लिए आर्थिक मदद जुटाने की कोशिश कर रहा था। एजेंसी को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में बैठे समर्थकों से भी संपर्क बनाए हुए था।

जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि संगठित नेटवर्क के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, भर्ती, प्रचार सामग्री और स्थानीय नेटवर्क को सक्रिय रखने में किया जा सकता था। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस नेटवर्क का संबंध सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों और उनके हैंडलरों से था।

सूत्रों के अनुसार एजेंसियों को कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं, जिनमें संदिग्ध संचार, वित्तीय लेनदेन और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब इन डाटा की तकनीकी जांच कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क की संरचना और उसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के वित्तीय ढांचे को कमजोर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अलगाववादी संगठनों, हवाला नेटवर्क और संदिग्ध ट्रस्टों पर लगातार कार्रवाई की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवाद को केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक स्रोतों को खत्म करके भी कमजोर किया जा सकता है।

कर्नाटक में सत्ता संतुलन की नई चाल, सिद्धारमैया से छीना योजना विभाग

बंगलूरू। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री Siddaramaiah से योजना और सांख्यिकी विभाग वापस ले लिया है। यह विभाग अब कैबिनेट मंत्री K. Venkatesh को सौंप दिया गया है। सरकार के इस फैसले को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन और राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राज्यपाल Thawar Chand Gehlot की मंजूरी के बाद यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार योजना और सांख्यिकी विभाग अब के. वेंकटेश के पास रहेगा, जो पहले से पशुपालन और रेशम विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वेंकटेश का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व सरकार के भीतर और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य की विकास योजनाओं, आंकड़ा आधारित नीति निर्माण

और बजटीय प्राथमिकताओं में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है।

हालांकि योजना और सांख्यिकी विभाग हटाए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास अब भी कई अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग बने हुए हैं। इनमें वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर), खुफिया विभाग, सूचना, युवा सेवाएं, खेल, अनुसूचित जनजाति कल्याण और सहकारिता जैसे विभाग शामिल हैं। इसके अलावा जिन विभागों का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, वे भी मुख्यमंत्री के ही पास रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विभागीय फेरबदल के बावजूद सिद्धारमैया सरकार और प्रशासन के सबसे शक्तिशाली केंद्र बने हुए हैं।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर किया गया है। अधिसूचना 24 मई 2026 को जारी की गई और अगले दिन कर्नाटक गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की गई। इस बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ जानकार इसे प्रशासनिक कार्यभार कम करने का प्रयास बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे कांग्रेस सरकार के भीतर शक्ति संतुलन की रणनीति के रूप में देख रहे हैं।

कर्नाटक कांग्रेस में पिछले कुछ समय से नेतृत्व और सत्ता संतुलन को लेकर चर्चाएं लगातार होती रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी समय-समय पर अटकलें लगती रही हैं। ऐसे में योजना और सांख्यिकी जैसे अहम विभाग का दूसरे मंत्री को सौंपा जाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संकेत दिए हैं कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व की ओर से नई दिल्ली बुलाया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मंगलवार सुबह 11 बजे पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक निर्धारित है, लेकिन अभी तक उन्हें बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह सूचना Mallikarjun Kharge के कार्यालय से मिली है।

दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक रणनीति और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा कर सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से बैठक के उद्देश्य की जानकारी सामने नहीं आई है।

असम में यूसीसी की दस्तक, विधानसभा में पेश विधेयक से तेज हुई राजनीतिक बहस

गुवाहाटी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर देश में चल रही बहस के बीच असम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। इसके साथ ही असम, Uttarakhand और Gujarat के बाद यूसीसी विधेयक लाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की ओर से संसदीय कार्य मंत्री Atul Bora ने विधानसभा में "असम समान नागरिक संहिता विधेयक 2026" पेश किया। विधेयक पेश होते ही विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस तेज हो गई। जहां सरकार इसे सामाजिक सुधार और कानूनी समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे भाजपा का राजनीतिक एजेंडा करार देकर व्यापक परामर्श की मांग कर रहा है।

सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक में

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों को एकीकृत और सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक में बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाने के लिए ऐसे संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य बनाने की बात कही गई है। सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, कानूनी स्पष्टता और पारिवारिक विवादों में कमी लाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाकर नागरिकों को समान कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधेयक में विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की जा सके।

हालांकि सरकार ने विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि यह कानून राज्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि असम की सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि असम की परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं और सरकार उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधेयक विवाह और सामाजिक परंपराओं को मौजूदा धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न करने की अनुमति देता है, इसलिए किसी समुदाय की सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

विधानसभा में विधेयक पेश होते ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। Indian National Congress, Trinamool Congress और रायजोर दल समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने इतना बड़ा कानून लाने से पहले सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से पर्याप्त चर्चा नहीं की। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी जैसा संवेदनशील मुद्दा केवल राजनीतिक बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक सहमति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष Jakir Hussain Sikdar ने यूसीसी विधेयक की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि राज्य की जनता को इससे वास्तविक लाभ क्या होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। सिकदर ने कहा कि असम जैसे बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक राज्य में ऐसा कानून लाने से पहले व्यापक जनसंवाद होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष और सामाजिक संगठनों की राय लिए बिना जल्दबाजी में विधेयक पेश किया है।

सिकदर ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले से आर्थिक दबाव झेल रही है, लेकिन सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को पहले जनता की आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

यूसीसी विधेयक को लेकर सामाजिक और कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी बहस तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा और समान अधिकार मिल सकते हैं, जबकि दूसरी ओर कई लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं।

संपादकीय

रुपये की गिरावट

यूं देश के आयात-निर्यात असंतुलन के चलते पिछले दो दशकों से रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में इस गिरावट में तेजी आई है। खासकर ईरान-अमेरिकी युद्ध शुरू होने के बाद इसमें छह फीसदी की चिंताजनक गिरावट आई है। जो हमारी आयात पर अत्यधिक निर्भरता को ही दर्शाता है। यद्यपि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसे मुद्रा संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया गिरावट हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल, यह गिरावट भू-राजनीतिक अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता से मुद्रास्फीति और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बीच हो रही है। इन दबावों ने मिलकर एक ऐसा संवेदनशील वातावरण बनाया है, जिसमें रुपये की कमजोरी व्यापक आर्थिक व्यवधानों को जन्म दे रही है। वैसे तो बढ़ता आयात असंतुलन ही रुपये की गिरावट के मूल में है। सबसे बड़ा संकट तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता का है, जो करीब 88 फीसदी है। इसके अलावा खाद्य तेल, उर्वरक आदि आवश्यक वस्तुओं का आयात लगातार बढ़ा है। वहीं रुपये के डॉलर के मुकाबले लगातार गिरने से ये वस्तुएं महंगी हो गई हैं। खासकर ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर परिवहन, मालभाड़ा वृद्धि, भोजन और घरेलू खर्चों पर पड़ा है। इसके चलते रुपये के अवमूल्यन से कंपनियां तथा देश के नीति-निर्माता भी खासे चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा में ऋण लेने वाली भारतीय कंपनियों पर ऋण चुकाने का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है।

दरअसल, इन सभी कारणों से बढ़ते व्यापार घाटे का चालू खाते के घाटे पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। जिसके चलते शेयर बाजार में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। वास्तव में विदेशी निवेशक अनिश्चितता के वातावरण में सुरक्षित अमेरिकी कंपनियों में निवेश बढ़ा रहे हैं। फलतः अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश में लगातार निकासी का रुझान देखा जा रहा है। जिसने हमारी आर्थिक चिंताओं को और बढ़ाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस जारी अस्थिरता को कम करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से हस्तक्षेप किया है, लेकिन ऐसे उपाय महज गिरावट की गति को कम करने के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने तर्क दिया है कि रुपये का स्वाभाविक रूप से अवमूल्यन करने से समय के साथ व्यापार असंतुलन को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने केंद्रीय बैंक से आग्रह किया है कि वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण होने वाले मुद्रा के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिये विशिष्ट विनिमय दर लक्ष्यों मसलन सौ रुपये प्रति डॉलर से आगे बढ़कर विचार करना चाहिए। हालांकि, अनियंत्रित अवमूल्यन से गंभीर जोखिम भी पैदा हो सकते हैं। देश के नीति-निर्माताओं को बाजार समायोजन की अनुमति देने और अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के बीच सावधानी से संतुलन बनाने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से सरकार की ओर से मुद्रास्फीति का कुशल प्रबंधन और अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा बनाये रखना, देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है।

भारत और साइप्रस के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी समझौतों के कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मायने

> “ यूरोप में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है। ऐसे में भारत को यूरोप के भीतर एक भरोसेमंद सहयोगी मिल रहा है। साइप्रस ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (India-EU Free Trade Agreement) को आगे बढ़ाने का समर्थन भी किया है। इसका अर्थ है कि भारत की यूरोप तक आर्थिक पहुँच मजबूत होगी।

भारत और साइप्रस के बीच हाल में हुई रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न समझौतों के कई बड़े कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मायने हैं। देखा जाए तो यह केवल द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि यूरोप, भूमध्यसागर, पश्चिम एशिया और वैश्विक शक्ति-संतुलन से भी जुड़ा कदम माना जा रहा है। चूंकि तुर्की और साइप्रस के बीच गहरी दुश्मनी है, इसलिए भारत उसे तुर्किये के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तुर्किये भारत के चिर शत्रु पाकिस्तान का मित्र है। इस प्रकार भारत के रणनीतिकारों ने एक तीर से कई शिकार किये हैं। उल्लेखनीय है कि साइप्रस एक द्वीप है, इसलिए उसकी लैंड बॉर्डर तुर्की के साथ नहीं लगती है। लेकिन समुद्री मार्ग से साइप्रस और तुर्की के बीच की दूरी महज 65 से 70 किलोमीटर है। यही नहीं, साइप्रस तुर्की से 85 गुना छोटा देश है। इसलिए तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। चूंकि तुर्की तो साइप्रस को एक देश भी नहीं मानता। लिहाजा दोनों देशों के बीच टकराव हमेशा बना रहता है। गत दिनों उसी देश साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स दिल्ली के दौरे पर आए। इस दौरान भारत और साइप्रस के बीच 14 मुद्दों पर ऐतिहासिक डील फाइनल हो गई।

आइए अब हम आपको इन 14 डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझिए आखिर में ये प्रमुख डील और समझौते क्या हैं? तो यह जान लीजिए कि भारत और साइप्रस ने संबंधों को “स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप” (Strategic Partnership) तक उन्नत किया है। जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग रोडमैप, आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यसमूह, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार से जुड़े कई समझौते हुए हैं।

लिहाजा, इनके कूटनीतिक मायने बेहद अहम हैं:-

पहला, यूरोप में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है। ऐसे में भारत को यूरोप के भीतर एक भरोसेमंद सहयोगी मिल रहा है। साइप्रस ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (India-EU Free Trade Agreement) को आगे बढ़ाने का समर्थन भी किया है। इसका अर्थ है कि भारत की यूरोप तक आर्थिक पहुँच मजबूत होगी। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाज़ार के दरवाजे और खुल सकते हैं। वहीं भारत की कूटनीतिक आवाज़ ईयू (EU) मंचों पर अधिक प्रभावी हो सकती है।

दूसरा, तुर्किये-पाकिस्तान समीकरण का संतुलन तोड़ने में अब भारत को मिलेगी सहूलियत, क्योंकि साइप्रस और तुर्किये के बीच लंबे समय से तनाव है। दूसरी ओर तुर्किये कई बार पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहा है। ऐसे में भारत-साइप्रस निकटता को एक भू-राजनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन दोहराया, जबकि साइप्रस भारत के आतंकवाद विरोधी रुख के करीब दिखा।

तीसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत, साइप्रस और यूरोप के बीच बढ़ती साझेदारी को चीन की Belt and Road रणनीति के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषकर समुद्री व्यापार, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है।

चौथा, आईएमईसी (IMEC) कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भारत की बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। खास बात यह कि साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर में स्थित होने के कारण इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और समुद्री केंद्र बन सकता है। इससे भारत का यूरोप तक व्यापार तेज हो सकता है, स्वेज नहर पर निर्भरता कुछ हद तक घट सकती है, और चीन समर्थित समुद्री नेटवर्क का विकल्प तैयार हो सकता है।

पांचवां, समुद्री और रक्षा सहयोग बढ़ेगा, क्योंकि दोनों देशों ने रक्षा रोडमैप और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया है। इसके मायने हिंद महासागर से लेकर भूमध्यसागर तक भारत की रणनीतिक उपस्थिति बढ़ सकती है। इससे साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नेटवर्क मजबूत होंगे, जिससे भारतीय नौसैनिक पहुँच को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।

छठा, भारत की “मल्टी-अलाइनमेंट” नीति को मजबूती मिलेगी। चूंकि भारत अब केवल एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए रूस, अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और भूमध्यसागरीय देशों के साथ समानांतर संबंध बनाकर भारत वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी स्वतंत्र स्थिति मजबूत कर रहा है। साइप्रस के साथ समझौते इसी नीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।

इसके आर्थिक मायने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि निवेश दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, शिपिंग, फिनटेक, पर्यटन और स्टार्टअप सेक्टर में सहयोग बढ़ सकता है। साइप्रस भारतीय निवेश के लिए यूरोप का “गेटवे” बन सकता है। यह डील भारत के लिए बड़ा संदेश भी है, क्योंकि यह डील दिखाती है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि यूरोप, भूमध्यसागर, पश्चिम एशिया, और वैश्विक व्यापार मार्गों में भी अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक भूमिका बढ़ा रहा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत-साइप्रस समझौते केवल छोटे देश के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध नहीं हैं, बल्कि यूरोप में रणनीतिक प्रवेश, तुर्किये-पाकिस्तान-चीन समीकरण का संतुलन, IMEC कॉरिडोर की मजबूती, और वैश्विक शक्ति राजनीति में भारत की बढ़ती सक्रियता का संकेत हैं।

प्रेरणा

मानवता का असली धर्म

लाहौर के संतराम गवर्नमेंट कॉलेज का वातावरण उस समय सामाजिक भेदभाव और ऊंच-नीच की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं था। समाज में जाति और छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी थीं कि पढ़े-लिखे युवक भी उससे प्रभावित थे। कॉलेज के छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन मन के भीतर कई पुरानी रूढ़ियां अब भी जीवित थीं। ऐसे ही माहौल में एक दिन एक छोटी-सी घटना घटी, जिसने न केवल एक छात्र की सोच बदल दी, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि तर्क और सत्य के सामने अंधविश्वास अधिक देर तक टिक नहीं सकता।

संतराम कॉलेज में बी.ए. के छात्र थे। वे अध्ययनशील होने के साथ-साथ तार्किक विचारों वाले युवक थे। समाज में फैली कुरीतियों और छुआछूत जैसी बुराइयों को वे मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति, वेशभूषा या जन्म से नहीं, बल्कि उसके विचारों और व्यवहार से होती है। वे अक्सर अपने साथियों से इस विषय पर चर्चा किया करते थे, लेकिन अधिकांश छात्र परंपरागत मान्यताओं के कारण उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे।

एक दिन कॉलेज के भोजन कक्ष में सभी छात्र भोजन कर रहे थे। वातावरण सामान्य था। उसी समय संतराम भी भोजन करने पहुंचे। वहां एक छात्र पास में बैठकर खाना खा रहा था, जो छुआछूत की भावना में गहरे डूबा हुआ था। संतराम ने उसकी मानसिकता को समझ लिया। वे जानते थे कि केवल उपदेश देने से उसकी सोच नहीं बदलेगी। इसलिए उन्होंने उसे तर्क के माध्यम से सत्य का अनुभव कराने का निश्चय किया।

भोजन करते समय संतराम जान-बूझकर उस छात्र से हल्के से छू गए। बस इतना होना था कि वह छात्र अचानक क्रोधित हो उठा। उसके चेहरे पर घृणा और आक्रोश साफ दिखाई देने लगा। वह तुरंत अपनी थाली छोड़कर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, “संतू मुझसे छू गया है। अब यह भोजन अशुद्ध हो गया। मेरी थाली का खर्च इसके नाम लिख देना।” उसकी बात सुनकर भोजन कक्ष में बैठे कई छात्र उसकी ओर देखने लगे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ स्थिति को गंभीरता से देख रहे थे।

लेकिन संतराम बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने क्रोध या अपमान का कोई भाव प्रकट नहीं किया। वे जानते थे कि यदि भावनाओं में बहकर उत्तर दिया जाए, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने तुरंत उस छात्र की बांह पकड़ ली और उसे वहीं बैठाकर बोले, “पहले अपनी यह क्रिस्टल टोपी उतारो और इसे उल्टा रखो।”

छात्र कुछ हैरान हुआ, लेकिन आसपास बैठे लोगों की उत्सुकता देखकर उसने टोपी उतार दी। संतराम ने शांत स्वर में पूछा, “बताओ, इसके भीतर जो पट्टी लगी है, वह किस चीज की बनी है?” छात्र ने सहज भाव से उत्तर दिया, “खाल की।”

संतराम मुस्कुराए और बोले, “तो क्या मैं इस मरी हुई खाल से भी अधिक अछूत हूं, जिसके कारण तुम भोजन छोड़कर भाग रहे हो? इस टोपी में लगी खाल को तुम सम्मान के साथ अपने सिर पर लगाए घूमते हो, लेकिन एक जीवित मनुष्य का स्पर्श तुम्हें अपवित्र लग रहा है। क्या यह बुद्धिमानी है?”

उनकी बात सुनते ही छात्र का चेहरा उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे। भोजन कक्ष में बैठे अन्य छात्र भी अब गंभीर हो चुके थे। संतराम ने आगे कहा, “भोजन की पवित्रता किसी व्यक्ति के छूने या न छूने से नहीं होती। भोजन की वास्तविक पवित्रता उसके सात्विक होने में होती है। यदि भोजन शुद्ध और सात्विक होगा, तो उससे विचार भी सात्विक बनेंगे। लेकिन यदि मन में घृणा, अहंकार और भेदभाव भरा हो, तो सबसे उत्तम भोजन भी मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकता।”

उनके शब्दों में कठोरता नहीं थी, बल्कि गहरी संवेदना और सच्चाई थी। छात्र के भीतर जैसे कोई दीवार टूटने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से बिना सोचे-समझे एक ऐसी परंपरा का पालन कर रहा था, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। उसने धीरे से अपनी थाली वापस उठाई और पुनः बैठकर भोजन करने लगा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि आत्मग्लानि और समझदारी का भाव था।

उस दिन के बाद दोनों छात्रों के बीच गहरी मित्रता हो गई। वह छात्र, जो पहले छुआछूत को धर्म समझता था, अब मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानने लगा। उसने महसूस किया कि किसी मनुष्य को जन्म या जाति के आधार पर छोटा समझना सबसे बड़ी अज्ञानता है। सच्ची श्रेष्ठता मनुष्य के चरित्र, व्यवहार और विचारों में होती है।

यह घटना केवल दो छात्रों के बीच हुई बहस नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक गहरा संदेश थी। छुआछूत जैसी कुरीतियां मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। वे समाज में घृणा, भेदभाव और अन्याय को जन्म देती हैं। जब तक मनुष्य दूसरों को अपने समान नहीं मानेगा, तब तक वास्तविक समानता और भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता।

संतराम ने उस दिन किसी बड़े मंच से भाषण नहीं दिया था, लेकिन उनके कुछ तार्किक शब्दों ने एक व्यक्ति की सोच बदल दी। यही सच्चे सुधारक की पहचान होती है। वे समाज को बदलने के लिए हिंसा या कटुता का सहारा नहीं लेते, बल्कि तर्क, प्रेम और संवेदना के माध्यम से लोगों के भीतर जागृति लाते हैं। आज भी समाज में कई प्रकार के भेदभाव दिखाई देते हैं। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं आर्थिक स्थिति के आधार पर लोग एक-दूसरे को छोटा समझते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि मानवता हमेशा उन लोगों के कारण आगे बढ़ी है, जिन्होंने समानता और प्रेम का संदेश दिया। मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से तय होता है, न कि उसके जन्म से। संतराम की यह छोटी-सी घटना हमें यह शिक्षा देती है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों को केवल तर्क और समझदारी से ही समाप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य अपने भीतर मानवता, करुणा और समानता का भाव विकसित कर ले, तो समाज की अनेक समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। सच्चा धर्म वही है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, न कि अलग करता है।

हर समस्या देती है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर

अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो असंख्य लोग बिना सोचे-समझे बोल देंगे कि ‘आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, अराजकता, उन्माद और बेरोजगारी ने जीवन मुश्किल कर दिया है।’ जब असंख्य लोगों की सोच नकारात्मक पहलुओं को लेकर एक जैसी हो जाती है, तो यह चिंता का विषय बन जाती है।

धरती पर विविध प्राणी निवास करते हैं। यह वसुधा प्राणियों के लिए एक ऐसा आंचल है, जिसकी छांव तले वे अपने परिवार के साथ जीवनयापन करते हैं। मगर जब उस आंचल पर आंच आने लगे, तो निस्संदेह डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्या किया जाए? क्या पूरी तरह निराश होकर बैठा जाए या फिर अंध-आशावाद में दिनों को गिना जाए?

इन दोनों ही तरीकों को अपनाने से मुश्किलें बढ़ेंगी, मगर हां, इन दोनों के बीच के तरीके को अपनाकर वसुधा के आंचल को बचाया जा सकता है। वह बीच का रास्ता है ‘मेलियोरिज्म’।

मेलियोरिज्म एक ऐसा विचार है, जो कहता है कि दुनिया को मानवीय प्रयासों से बेहतर बनाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो मेलियोरिज्म आशावाद और निराशावाद के बीच का मार्ग है, जिससे ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। जब व्यक्ति ‘सक्रिय सुधारवाद’ की ओर बढ़ेगा, तो खुशियों की नदियों को हर ओर फैलाया जा सकता है।

हमारे बीच कई ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने नई सोच से ‘मेलियोरिज्म’ शब्द को सार्थक कर दिया और समाज में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई। सुनील जागलान एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। वे बीबीपुर गांव के सरपंच थे। वर्ष 2012 में जब उनके यहां बेटी हुई, तो अस्पताल में नर्सों ने उनकी बेटी के जन्म पर मिठाई लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने का निर्णय कर लिया। उन्होंने ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान शुरू किया। उनका यह अभियान धीरे-धीरे हरियाणा के कई गांवों में फैल गया। लोगों ने महसूस किया कि सचमुच बेटियों को आगे बढ़ाने का जज़्बा उनमें भी नई उमंगें जगा देता है। धीरे-धीरे ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान नए-नए रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में ही एक गांव है — खेड़ा गनी। इस गांव में शिक्षित लड़कियों की नेमप्लेट उनके घर-आंगन में सजने लगी है और हर घर की पहचान वहां की लड़की के नाम से होने लगी है। ‘बेटी हूं बेटी बोलो’ अभियान ने भी लोगों को जागरूक किया। बेटियों का भी अपना अस्तित्व होता है। ऐसे में उन्हें बेटा कहकर क्यों पुकारा जाए? उनके इन अभियानों ने लोगों की सोच को बदल दिया। अब लोगों ने अपनी लड़कियों के ‘भतेरी’, ‘काफी’, ‘अंतिम’ जैसे नाम भी रखने बंद कर दिए हैं। इसी तरह के छोटे प्रयास नए बदलाव की लहर लाते हैं और पुरानी कुप्रथाएं बंद हो जाती हैं।

इस विचार को हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है। उसके लिए बस स्वयं के साथ कुछ संकल्प लेने हैं, जैसे—

निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें— आज प्रत्येक व्यक्ति ‘शॉर्टकट’ अपनाकर सफलता पाना चाहता है, मगर सफलता का कोई ‘शॉर्टकट’ नहीं होता। लगातार और रोज थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते रहें। फिर सफलता की सीढ़ी अपने आप खड़ी होती जाती है। एक दिन व्यक्ति को विजय की सीढ़ी पर होता है।

समस्याओं को अवसर के रूप में देखें— जब व्यक्ति हर काम को समस्या मानने लग जाता है, तो वास्तव में समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या अवसर का दूसरा रूप होती है। ड्यूक एलिंगटन का कहना है कि ‘समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर है।’ इसलिए इस अवसर को सहजता, धैर्य और विश्वास के साथ हल करें। जब एक बार आप समस्या को अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे, तो फिर समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। वह आपके पास अवसर का रूप लेकर आएगी और आपको दिन-प्रतिदिन बेहतर बनाएगी।

अक्सर कई लोग इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि वे कार्य करते समय पूर्ण एकाग्र नहीं होते। एकाग्रता ही सर्वश्रेष्ठ कार्य की कुंजी है। टॉम कॉनेलन अपनी पुस्तक ‘एक प्रतिशत फ़ॉर्मूला’ में कहते हैं कि ‘शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों को अलग करने वाली चीज यह है कि वे दिन भर एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य-लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं।’

सही मायने में मैदान पर डटे रहने में ही असली सुख है। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी जो मैदान छोड़ने से इंकार कर देता है, तो फिर विपरीत परिस्थितियां ही उसके लिए प्रगति, खुशी और सुख की नींव रचती हैं। बस इसके लिए थोड़ा-सा अपने व्यक्तित्व को ‘मेलियोरिज्म’ में ढालना होता है।

अभियान

भक्ति, आस्था और लोककल्याण की अमृतधारा है गंगा दशहरा

भारतीय संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवन, करुणा और मातृत्व का स्वरूप समझा गया है। इन्हीं पवित्र नदियों में मां गंगा का स्थान सर्वोच्च है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का सबसे विराट प्रतीक यदि कोई है, तो वह गंगा ही है। हिमालय की गोद से निकलकर करोड़ों लोगों के जीवन को सींचने वाली गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा है। इसी कारण गंगा दशहरा का पर्व भारतीय लोकजीवन में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, लोककल्याण की भावना, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का भी महापर्व है।

ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा उस पावन क्षण की स्मृति में आयोजित होता है, जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। मान्यता है कि इसी दिन गंगा की पवित्र धारा ने पृथ्वी को स्पर्श कर मानव जीवन को शुद्धता, मोक्ष और नई चेतना का संदेश दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा। यह तिथि 25 मई को प्रातः 4:30 बजे से प्रारंभ होकर 26 मई को प्रातः 5:10 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के कारण पर्व 25 मई को ही मनाया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार गंगा दशहरा सोमवार को पड़ रहा है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे इस पर्व की आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है।

गंगा अवतरण की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ वर्णित है। कहा जाता है कि राजा सगर के साठ हजार पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए वर्षों तक कोई उपाय नहीं मिल सका। तब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन और निष्काम थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। अंततः मां गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुईं, किंतु उनका वेग अत्यंत प्रचंड था। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरतीं, तो संपूर्ण धरती जलमग्न हो सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने करुणा दिखाते हुए गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे-धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही घटना गंगा अवतरण कहलाती है।

यह कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का गहरा संदेश भी देती है। भगीरथ की तपस्या त्याग, धैर्य और लोककल्याण की भावना का प्रतीक है। वहीं भगवान शिव का गंगा को धारण करना यह बताता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही सृष्टि को सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए भारतीय समाज में किसी महान प्रयास को आज भी “भगीरथ प्रयत्न” कहा जाता है।

गंगा दशहरा को लेकर हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के दस प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ‘दश’ अर्थात दस और ‘हरा’ अर्थात हरने वाली। इसी कारण इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान-पुण्य, जप, तप और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, ऋषिकेश और गंगासागर जैसे तीर्थस्थलों पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। गंगा तटों पर दीपदान और भव्य आरती का दृश्य श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। संध्या के समय जब हजारों दीप गंगा की लहरों पर तैरते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवत्व पृथ्वी पर उतर आया हो।

गंगा दशहरा का संबंध भगवान शिव से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चूंकि गंगा उनकी जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं, इसलिए इस दिन शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा मोक्ष की कामना करते हैं। हिंदू परंपरा में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में इसका प्रयोग होता है। विवाह, यज्ञ, पूजा और अंतिम संस्कार तक में गंगा जल को शुद्धता और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही कारण है कि गंगा केवल नदी नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की जीवंत धारा मानी जाती है।

भारतीय साहित्य और लोकसंस्कृति में भी गंगा का विशेष स्थान है। संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जैसे महान कवियों ने अपने काव्य में गंगा की महिमा का वर्णन किया है। गांवों में लोग गंगा जल हाथ में लेकर सत्य बोलने की शपथ लेते रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि गंगा की साक्षी में असत्य नहीं बोला जा सकता। यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक चेतना का प्रतीक भी है।

गंगा दशहरा के अवसर पर देश के अनेक हिस्सों में मेले लगते हैं। ऋषिकेश से लेकर गंगासागर तक भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथा-प्रवचन और भंडारों का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का माध्यम भी बन जाते हैं।

आधुनिक समय में गंगा दशहरा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जिस गंगा को हम मां कहकर पूजते हैं, वही आज प्रदूषण, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे की समस्या से जूझ रही है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण ने गंगा की निर्मलता को प्रभावित किया है। अनेक स्थानों पर गंगा का जल प्रदूषित हो चुका है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में गंगा दशहरा हमें केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है।

पिछले कुछ वर्षों में अनेक स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संस्थाएं गंगा तटों की सफाई के लिए अभियान चला रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर लोग स्वच्छता अभियान में भाग लेकर यह संकल्प लेते हैं कि वे नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे। यह पहल बताती है कि सच्ची भक्ति केवल आरती और पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रकृति की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम गंगा को मां मानते हैं, तो उसकी स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गंगा दशहरा जैसे पर्व मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। आधुनिक जीवनशैली में मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि वह प्रकृति और आत्मिक चेतना से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में गंगा दशहरा हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल धन और उपलब्धियों का नाम नहीं है। मन की शांति, प्रकृति के प्रति सम्मान और आध्यात्मिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक हैं।

गंगा भारतीय सभ्यता की जीवनरेखा है। उसकी धारा केवल खेतों को नहीं सींचती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति को भी जीवित रखती है। हिमालय से निकलकर समुद्र तक पहुंचने वाली गंगा भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसकी गोद में अनेक नगर बसे, अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं और असंख्य संतों-महात्माओं ने आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया।

इसलिए गंगा दशहरा को केवल एक धार्मिक पर्व के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति, लोकआस्था, पर्यावरण चेतना और आध्यात्मिक संतुलन का विराट उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि पूजनीय है। जिस समाज में नदियों को मां कहा जाता है, वहां पर्यावरण संरक्षण केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि धर्म बन जाता है।

गंगा दशहरा का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर पवित्रता, करुणा और समर्पण की भावना विकसित करे। जिस प्रकार मां गंगा बिना किसी भेदभाव के सभी को जल प्रदान करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रेम, सेवा और लोककल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है और यही गंगा दशहरा की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा भी।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

श्रम मंत्री कांतिलाल ने किया कमाल! दस लाख पेड़ लगाकर मोरबी को बनाया हरा-भरा

▶▶ कांतिलाल ने कैंसर से नहीं मानी हार, शेष जीवन प्रकृति की गोद में समर्पित करने का संकल्प किया

▶▶ 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े वन कवच 'नमो वन' का लोकार्पण किया था

▶▶ हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने एक बार फिर इस नमो वन का दौरा किया और 3 करोड़ रुपए के खर्च से आइकॉनिक रोड बनाने के लिए विशेष ग्रांट आवंटित की, ताकि लोग इस वन का आनंद उठा सकें

▶▶ मोरबी के विधायक हैं श्री कांतिलाल अमृतिया, 2025 में मच्छू डैम-2 के किनारे 1200 बीघा जमीन पर दस लाख पेड़ लगाकर बंजर भूमि को जंगल में बदला

गांधीनगर : बमुश्किल आठ महीने पहले तक मोरबी, जो भारत का सिरेमिक हब है, के बाहरी इलाके में मच्छू डैम-2 के किनारे श्री मोरबी पांजरापोल ट्रस्ट के स्वामित्व वाली 1200 बीघा की विशाल बंजर जमीन उपेक्षित हालत में थी। आज वही जमीन राज्य के श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिलाल अमृतिया के अथक प्रयासों से 'नमो वन' में बदल गई है। गत वर्ष सितंबर में लगाए गए दस लाख से अधिक पौधों के कारण आज इस बंजर जमीन ने हरियाली की चुनर ओढ़ ली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर इस वन कवच (नमो वन) का लोकार्पण किया था। आठ महीने पहले जो इलाका वीरान और बंजर था, आज वहां हरियाली लहलहा रही है।

श्री कांतिलाल अमृतिया, जिन्हें लोग प्यार से 'काना भाई' कहकर बुलाते हैं, सौराष्ट्र की सबसे बड़ी मानी जाने वाली श्री मोरबी पांजरापोल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इस ट्रस्ट के पास 4500 बीघा जमीन है। पर्यावरण को बचाने और समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य करने की सोच के साथ कांतिलाल अमृतिया ने इस बंजर भूमि की तस्वीर बदलने का भगीरथ कार्य शुरू किया और गुजरात का सबसे बड़ा 'वन कवच' (नमो वन) बनाने का दृढ़ निश्चय किया।

उन्होंने मच्छू डैम-2 के किनारे स्थित ट्रस्ट की 1200 बीघा जमीन पर दस लाख पेड़ लगाने का बड़ा अभियान शुरू किया। इससे पहले, उन्होंने मच्छू डैम के किनारे आठ चेकडैम बनाए हैं और जल संचय करने का उत्कृष्ट कार्य किया है।

500 लोगों ने रोज 25 से 30 हजार पौधे लगाए

अभियान के शुरुआती दौर की यादों को ताजा करते हुए श्री कांतिलाल अमृतिया ने बताया, "जब हमने एक महीने में दस लाख पौधे लगाने का निर्णय किया, तब पौधरोपण के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाली संस्था सद्भावना वृद्धाश्रम की मदद से एक विस्तृत योजना बनाई।"

श्री अमृतिया ने आगे कहा, "हमने अपने इस यज्ञ में सद्भावना वृद्धाश्रम को शामिल किया। चूंकि जमीन अनुपजाऊ और बंजर थी, इसलिए सबसे पहले उसे समतल किया। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बाहर से हजारों टन उर्वर मिट्टी लाकर यहां लाकर डाली, साथ ही बड़ी मात्रा में गोबर खाद डालकर जमीन को उपजाऊ बनाया। 1200 बीघा जमीन के चारों ओर बाड़ लगाई। इसके बाद पौधरोपण के लिए एक साथ 500 लोगों ने साथ मिलकर रोजाना लगभग 25 से 30 हजार पौधे लगाने का भगीरथ कार्य शुरू किया। केवल 37 दिनों के अथक प्रयासों के बाद हम 10 लाख पौधे लगाने में सफल रहे।" 17 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मोरबी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किया 'नमो वन' का लोकार्पण किया

कांतिलाल अमृतिया ने कहा कि दस लाख पौधों को नियमित रूप से खाद-पानी देने की व्यवस्था की गई है। इसका प्रबंधन सद्भावना वृद्धाश्रम करता है। आज, आठ महीने के बाद ये दस लाख पौधे अब पेड़ों में बदल गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आइकॉनिक रोड बनाने के लिए तीन करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट आवंटित की

श्री कांतिलाल अमृतिया ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भी हमारे इस काम में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। हाल में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले उन्होंने दूसरी बार 'नमो वन' का दौरा किया। उन्होंने यहां एक आइकॉनिक रोड बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट आवंटित की है, ताकि लोग इस वन कवच तक पहुंच सकें और इसका आनंद उठा सकें।"

कांतिलाल ने कैंसर को हराया, अब शेष जीवन प्रकृति को समर्पित

64 वर्षीय श्री कांतिलाल अमृतिया ने हाल ही में कैंसर का पता चलने पर सर्जरी करवाई है। एक आम इनसान कैंसर का नाम सुनते ही हिम्मत हार जाता है, लेकिन कांतिलाल उनमें से नहीं हैं। पांच कीमोथेरेपी पूरी करने के बाद अभी वे इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं। इस मुश्किल हालात में भी उनका जनसंपर्क जारी है। उन्होंने कहा कि इस कैंसर से बचाकर प्रकृति ने उन्हें दूसरा जीवन दिया है और वे इस दूसरी जिंदगी प्रकृति को ही समर्पित करना चाहते हैं।

छह बार विधायक चुने गए श्री कांतिलाल अमृतिया ने शेष जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, "कैंसर की सर्जरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब मैं अपना जीवन प्राकृतिक कृषि और वृक्षारोपण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित करना चाहता हूं। हमने सरकार को पत्र लिखकर मच्छू डैम के किनारे स्थित सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की है, ताकि वहां भी इस प्रकार का विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सके।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई 'नागरिक देवो भव:' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में गुजरात का वन डे गवर्नेंस से व्हाट्सएप गवर्नेंस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को गति देकर नागरिकों को व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

▶▶ गुजरात सरकार और मेटा के बीच व्हाट्सएप आधारित सिटीजन सर्विस डिलीवरी को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू गांधीनगर में संपन्न हुआ

▶▶ लाइन से ऑनलाइन तक की सुगम डिजिटल पहल को गति देने वाला एमओयू

▶▶ ग्रामीण और शहरी नागरिकों को शिकायत निवारण सहित आय-जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड तथा आधिकारिक शपथपत्र जैसी लगभग 20 सरकारी सेवाएं एक ही व्हाट्सएप नंबर से घर बैठे मिल सकेंगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई 'नागरिक देवो भवः' की परिकल्पना को वन डे गवर्नेंस से व्हाट्सएप गवर्नेंस के माध्यम से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में राज्य सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के बीच एक एमओयू गांधीनगर में संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में राज्य सरकार ने जीएआरसी की सिफारिशों के अनुसार 'सुगम डिजिटल गुजरात' पहल के तहत पांच प्रमुख विभागों की लगभग 20 नागरिक केंद्रित सेवाएं व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं।

अब इन सेवाओं को लोगों के लिए अधिक सरल और तेज बनाने के साथ-साथ सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने में मेटा और राज्य सरकार के बीच हुआ यह एमओयू महत्वपूर्ण साबित होगा।

तद्नुसार; अंग्रेजी और गुजराती भाषा में व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट के जरिए राज्यभर के नागरिक एक ही व्हाट्सएप नंबर से इन 20 महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ आने वाले समय में घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही प्राप्त कर सकेंगे।

इतना ही नहीं; इन सेवाओं के लिए अलग-अलग वेब पोर्टल पर जाने या कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाकर लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता से भी आने वाले दिनों में मुक्ति मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा जो सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएंगी, उनमें शिकायत निवारण सहायता, आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड तथा आधिकारिक शपथपत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इस एमओयू के लागू होने से आने वाले समय में सेवा वितरण प्रक्रिया अधिक सरल होने के साथ-साथ रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग भी अधिक मजबूत होगी। राज्य सरकार आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से और अधिक सेवाओं को भी इस व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ने की मंशा रखती है।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू होने वाली इस नई व्हाट्सएप गवर्नेंस आधारित नागरिक केंद्रित सेवाओं का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। विशेष रूप से अब सरकारी सेवाएं अधिक आसान बनेंगी, सेवाएं मोबाइल पर कुछ ही क्लिक में उपलब्ध होंगी, समय और खर्च दोनों की बचत होगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक सुदृढ़ होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकार की सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी का लाभ अब आम आदमी तक घर बैठे पहुंचेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिक केंद्रित गवर्नेंस की जो दिशा दी है, उसमें गुजरात ने वन डे गवर्नेंस जैसी पहल के माध्यम से समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत कर सामान्य नागरिक को कम से कम परेशानी और अधिक से अधिक सुविधा मिले, इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में लगातार सफल प्रयास किए हैं।

शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में वीसीई आधारित व्यवस्था के माध्यम से लाखों नागरिकों तक सरकार की सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही हैं। अब मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक (मेटा) के साथ हुए इस एमओयू के जरिए गुजरात नागरिक केंद्रित गवर्नेंस के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है।

आने वाले समय में नागरिकों को अपने मोबाइल पर कुछ ही क्लिक में एंड टू एंड सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग और अधिक मजबूत होगा। केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ स्वरूप में उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव श्री हारित शुक्ला तथा मेटा के डायरेक्टर एवं हेड ऑफ पॉलिसीज श्री अमन जैन और कंट्री डायरेक्टर श्री ए. श्रीनिवास ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक-दूसरे को इसकी प्रति सौंपी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अंजु शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा सचिव डॉ. अजय कुमार भी उपस्थित रहे।

धोलेरा की रफ्तार को मिला सरकारी भरोसा, विकास कार्यों की समीक्षा में दिखा 'विकसित भारत' का विजन

धोलेरा। गुजरात का महत्वाकांक्षी औद्योगिक और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट धोलेरा अब तेजी से देश के सबसे बड़े निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रों में अपनी पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के उप मुख्यमंत्री Harsh Sanghavi ने शनिवार को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) का विस्तृत दौरा कर यहां चल रहे विकास कार्यों और औद्योगिक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकसित किए जा रहे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी सुविधाओं और औद्योगिक परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और डेवलपर्स से प्रगति रिपोर्ट ली। दौरे को धोलेरा के विकास की दिशा में सरकार की बढ़ती प्राथमिकता और 'विकसित भारत 2047' के विजन से जोड़कर देखा जा रहा है।

धोलेरा को भविष्य के औद्योगिक और शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार बड़े स्तर पर निवेश और आधारभूत संरचना तैयार करने में जुटी हैं। उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौड़, उद्योग सचिव ममता वर्मा, पर्यटन सचिव एवं डीआईसीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप आर्य और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रुशिन भट्ट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने धोलेरा में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल गतिविधियों और आने वाले निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक्टिवेशन एरिया में विकसित किए जा रहे GAP ग्रुप के बहुचर्चित अखिलम टाउनशिप प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। GAP ग्रुप के चेयरमैन Gopal Goswami, मैनेजिंग डायरेक्टर Ambarish Parajiya और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पटेल ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें संकल्प पत्र, शंख और भगवद गीता की प्रति भेंट की गई। इसे 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय संकल्प और औद्योगिक विकास में सामूहिक भागीदारी का प्रतीक बताया गया।

GAP ग्रुप के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को अखिलम टाउनशिप प्रोजेक्ट की प्रगति और उसकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना धोलेरा में तेजी से बढ़ती रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। प्रोजेक्ट में आधुनिक स्टूडियो अपार्टमेंट्स, को-वर्किंग स्पेस, फूड कोर्ट और अन्य लाइफस्टाइल सुविधाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि यहां आने वाले उद्योगों, कर्मचारियों और निवेशकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने परियोजना की प्रगति और आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि धोलेरा में जिस गति से औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए गुणवत्तापूर्ण रिहायशी और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल उद्योग स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के लिए आधुनिक जीवनशैली, आवास और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने डेवलपर्स को परियोजना के कार्यान्वयन में और तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि आने वाले समय में उद्योगों की बढ़ती मांग को समय रहते पूरा किया जा सके।

हर्ष संघवी ने यह भी कहा कि धोलेरा में लगातार बढ़ रहे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के कारण निकट भविष्य में रेडी-टू-मूव घरों और आधुनिक टाउनशिप की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि धोलेरा आने वाले वर्षों में देश के सबसे बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में शामिल होगा, जहां रोजगार, निवेश और शहरी विकास के नए अवसर पैदा होंगे।

साइट विजिट के दौरान GAP ग्रुप के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को धोलेरा में तैयार किए जा रहे सबसे बड़े RCC राफ्ट फाउंडेशन निर्माण की जानकारी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्माण तकनीकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बड़े पैमाने पर किए जा रहे इंजीनियरिंग कार्यों के जरिए क्षेत्र में आधुनिक और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में उन्नत निर्माण तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले मानकों का पालन किया जा रहा है, ताकि आने वाले दशकों तक यह परियोजना औद्योगिक और शहरी विकास की जरूरतों को पूरा कर सके।

पश्चिम रेलवे द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026,अभियान के माध्यम से हरित पहल को प्रोत्साहन

मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा स्थिरता एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान, स्वच्छता गतिविधियाँ तथा पर्यावरण-अनुकूल पहलों का आयोजन

राष्ट्रव्यापी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के अंतर्गत, जिसे 15 मई से 5 जून, 2026 तक मनाया जा रहा है, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो, ईएमयू कार शेडों, रेलवे कॉलोनियों तथा अन्य रेलवे इकाइयों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न पहलें की गईं। इन गतिविधियों का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों एवं अन्य हितधारकों के बीच स्थिरता, स्वच्छता, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देना है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत सभी मंडलों में विश्व पर्यावरण दिवस गतिविधियों के शुभारंभ के साथ हुई। साथ ही #MissionLiFE तथा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 विषयों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण शपथ भी दिलाई गई, जिसमें कर्मचारियों एवं हितधारकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने तथा सतत भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर जलवायु परिवर्तन, सतत जीवनशैली तथा "सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहें" संदेश से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं डिजिटल संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। यात्रियों एवं रेलवे उपयोगकर्ताओं को पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतलों, पर्यावरण-अनुकूल बैगों तथा पुनः उपयोग योग्य कंटेनरों के उपयोग जैसी हरित आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। "अपनी पानी की बोतल स्वयं साथ रखें" संदेश के माध्यम से रेलवे परिसरों में प्लास्टिक कचरे को कम करने हेतु विशेष जन-जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा स्टेशनों, कोचिंग डिपो, ईएमयू कार शेडों तथा अन्य इकाइयों में प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाए गए। यात्रियों को पृथक कूड़ेदानों का सही उपयोग करने तथा स्वच्छ रेलवे वातावरण बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक किया गया। स्थानीय जनसमुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ रेलवे स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान भी आयोजित किए गए, जिससे स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिला।

इसके अतिरिक्त, रेलवे कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के लिए कार्यशालाएँ एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जलवायु कार्रवाई, उचित अपशिष्ट पृथक्करण, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग में कमी तथा दैनिक कार्यों में सतत पर्यावरणीय व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। मंडल द्वारा प्लास्टिक रहित, पर्यावरण-अनुकूल कटलरी एवं जैव-अपघटनीय विकल्पों को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही RailOne एवं अन्य ऑनलाइन अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग एवं पेपरलेस यात्रा को प्रोत्साहित कर कागज की खपत कम करने तथा सतत यात्रा पद्धतियों को समर्थन दिया गया।

इन पहलों के माध्यम से पश्चिम रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, स्वच्छता तथा जनभागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया है, जिससे स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल रेलवे प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

वायरल वीडियो मामले में अनंत सिंह को फिलहाल राहत, गिरफ्तारी पर रोक से बढ़ी राजनीतिक हलचल

गोपालगंज। हथियार लहराने और कथित अश्लील डांस के वायरल वीडियो मामले में मोकामा से जदयू विधायक Anant Singh को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मई तय की है। अदालत के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि मामला एक जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक मंच पर कथित हथियार प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।

इस मामले में विधायक अनंत सिंह समेत कुल नौ लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। हालांकि अदालत से फिलहाल केवल अनंत सिंह को ही अंतरिम राहत मिली है, जबकि अन्य आरोपितों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद आगे का आदेश पारित किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने अदालत में विधायक का पक्ष रखा। वकीलों ने दलील दी कि वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है और वीडियो की सत्यता तथा संदर्भ की गहन जांच अभी बाकी है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो संपादित हो सकता है और उसमें दिखाई गई घटनाओं को वास्तविकता से अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक विधायक को राहत दी जाए, क्योंकि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने सुनवाई के बाद बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 जोड़ने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल उस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष का मानना है कि मामले में लगाए गए आरोपों और कानूनी धाराओं की समीक्षा आवश्यक है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। यह पूरा मामला 3 मई को गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग कथित रूप से हथियार लहराते और मंच पर डांस करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू की गई। वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई थी, क्योंकि कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए गए थे।

घटना के बाद विधायक अनंत सिंह ने सफाई देते हुए कहा था कि कार्यक्रम स्थल से उनके निकलने के बाद क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया था कि वायरल वीडियो को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं और मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि जांच एजेंसियां उन्हें बुलाती हैं तो वह पूरा सहयोग करेंगे। मामले में अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इस मामले को कानून-व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से जोड़कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि जदयू नेताओं का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

अब सबकी नजर 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जब अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई और राहत को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। वायरल वीडियो और हथियार प्रदर्शन से जुड़ा यह मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और कानून-व्यवस्था पर बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को राहत, फिर भी रोज 600 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चार चरणों में हुई बढ़ोतरी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन वित्तीय दबाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के सामने बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रियायती एलपीजी वितरण और घरेलू बाजार में कीमतों को संतुलित रखने की चुनौती बनी हुई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि कीमतों में हालिया संशोधन के बाद तेल कंपनियों का दैनिक घाटा घटकर लगभग 600 करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने बताया कि 15 मई से पहले स्थिति कहीं अधिक गंभीर थी। उस समय पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था। लगातार बढ़ते घाटे के कारण तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा था और बाजार में ईंधन आपूर्ति तथा मूल्य संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। सरकार और तेल कंपनियों की ओर से चार चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी किए जाने के बाद घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार मूल्य संशोधन से कंपनियों को राहत मिली है, लेकिन घरेलू रसोई गैस एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी और रियायती दरों के कारण अब भी कंपनियों पर भारी वित्तीय बोझ बना हुआ है। सुझाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत और उपभोक्ताओं को तय रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाने के बीच का अंतर वहन करती है। इसके बावजूद तेल कंपनियों को कुल मिलाकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया that पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद एलपीजी पर जारी राहत योजनाओं के कारण घाटा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो आने वाले दिनों में घरेलू ईंधन कीमतों पर फिर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर सरकार महंगाई और आम जनता पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश में भी जुटी हुई है।

पश्चिम रेल्वे
लिफ़्ट की व्यवस्था

Sr.DEE/P/BCT ई-टेंडर नोटिस संख्या: EL-166-160-WA-84 (R-1) दिनांक 21-05-2026 (टू पेकेट सिस्टम) आमंत्रित करता है. कार्य और स्थान: मुंबई मंडल (गैर-उपनगरीय खंड):- स्टेशनों के फुट ओवर ब्रिजों पर लिफ्ट (27 नग) लगाने का प्रावधान (विद्युत और सिविल कार्य के लिए संयुक्त टेंडर)। कार्य की अनुमानित लागत: ₹17,09,47,471.81/- EMD: ₹34,19,000/- जमा करने की तिथि और समय: दि. 16.06.2026 को 15:00 बजे तक. खोलने की तिथि और समय: दि. 16.06.2026 को 15:30 बजे। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0152

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम
ई –निविदा सूचना

संख्या : W/623/5/3/NIT. दिनांक : 22/05/2026, मंडल रेल प्रबंधक मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम, निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाईट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है। **ई–टेंडरिंग** : RTM-2026-27-50, **कार्य का नाम** : दाहोद वर्कशॉप – रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप पर जीरो लेवल ट्रैक, पॉकेट लाइन और द्वितीय प्रवेश गेट का प्रावधान। **अनुमानित मात्रा** : टेंडर के अनुसार, **अनुमानित लागत** : ₹4,69,49,419.52/–, **बयाना राशि** : ₹9,39,000.00/– **कार्य समापन अवधि** : 18 महीने। कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कार्य, **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि** : 14/05/2026, **निविदा खुलने की तिथि** : 08/06/2026 • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। **SNP-073**

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम
ई –निविदा सूचना

संख्या : W/623/5/3/NIT. दिनांक : 21/05/2026, मंडल रेल प्रबंधक मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम, निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाईट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है। **ई–टेंडरिंग** : RTM-2025-26-103R2, **कार्य का नाम** : दाहोद स्टेशन – लिफ्ट (3 नग) के प्रावधान के संबंध में आरसीसी लिफ्ट वेल का निर्माण। **अनुमानित मात्रा** : टेंडर के अनुसार, **अनुमानित लागत** : ₹1,00,94,849.38/–, **बयाना राशि** : ₹201,900.00/– **कार्य समापन अवधि** : 12 महीने। **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि** : 20/05/2026, **निविदा खुलने की तिथि** : 15/06/2026 • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। **SNP-072**

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

पद्म पुरस्कारों की घोषणा: गुजरात के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, जनसंपर्क, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण सर्वोच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस दौरान गुजरात के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके विवरण इस प्रकार हैं:

श्री रतिलाल मोहनलाल बोरिसागर एक प्रसिद्ध गुजराती लेखक हैं जो अपने हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक लेखन के लिए जाने जाते हैं।

श्री बोरिसागर का जन्म 31 अगस्त, 1938 को गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनकी शैक्षणिक योग्यताएं एम.ए. (MA), बी.एड. (B.Ed.) और पी.एच.डी. (Ph.D.) हैं। एक शिक्षक के रूप में, उन्होंने 1957 से 1974 तक प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तरों पर अध्यापन कार्य किया। इसके बाद, उन्होंने 1974 में गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्यपुस्तक बोर्ड, गांधीनगर में शिक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। वे 1998 में इसी संस्था से उप निदेशक (शिक्षा) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

श्री बोरिसागर ने 1955 के आसपास लिखना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में छोटी कहानियाँ लिखीं, लेकिन बाद में उन्होंने हल्की शैली में निबंध लिखना शुरू कर दिया। अपनी पहली पुस्तक 'मरक मारक' (1977) के प्रकाशन के बाद उन्होंने हल्की-फुल्की शैली में ही लिखना जारी रखा। उनकी हल्की शैली की पुस्तकें हैं: 'मरक मारक' (1977); ' आनंद लोक' (1983); ' संभवामि युगे युगे' (1994); ' एन्जॉयोग्राफी' (1997); ' तिलक करूं त्रिसथ हुआ' (2002); ' जीएसटी-के' (2004); ' भज आनंदम' (2007); ' अमथुन अमथुन केम ना हंसी' (2008); ' ओम हक्कमम' (2010); ' भद्रंभद्र अमर छे' (2014); ' मोज-मान रहा रे' (2017); ' विनोद-ना वैकुंठ-मान' (2017); ' त्रिन पदैया अमेरिका-मान' (2019); ' एक नहीं लवेयेलो इंटरव्यू' (2022)। इसके अलावा, उन्होंने संस्मरणों की एक पुस्तक 'क्यां चे मारी नदी' (2021) भी लिखी है। उन्होंने ग्यारह संकलन पुस्तकें प्रकाशित की हैं (1998-2021)। उन्होंने भाषा के लिहाज से बकोर पटेल की पुरानी हास्य कहानियों की 33 पुस्तकों का संपादन किया है (2012-2013)। हरिप्रसाद व्यास द्वारा लिखित बकोर पटेल की कहानियाँ सत्तर वर्ष पहले प्रकाशित हुई थीं, इसलिए उन्हें आज के युवा पाठकों के लिए पठनीय बनाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार का कार्य गुजराती भाषा में अपनी तरह का पहला कार्य है। उन्होंने बच्चों के लिए दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं: 'महाभारत-ना-प्रसंग' (2002); ' श्रेष्ठ बाल खुमसिन' (2007)। उन्होंने बाल विकास पर 'बाल वंदना' (1994) नामक पुस्तक प्रकाशित की है। उन्होंने ' रमनभाई नीलकंठ' (2017) नामक जीवनी पुस्तक और 'गुजराती प्रतिकावियो' (2003) नामक आलोचना पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने गुजराती मासिक पत्रिका 'अखंड आनंद' (1999-2005) के संयुक्त संपादक के रूप में कार्य किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में श्री बोरिसागर का योगदान भी उल्लेखनीय है। उन्होंने 1957 से 1974 तक सोलह वर्षों तक सावरकुंडला (अमरेली-गुजरात) में प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान की। उन्होंने 1974 में सावरकुंडला छोड़ दिया। 36 वर्षों के बाद, उनके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों ने 2011 में सावरकुंडला में साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक संस्था की स्थापना की। वर्ष 2015 में, इस संस्था ने सावरकुंडला में 'श्री लल्लूभाई सेठ आरोग्य मंदिर' अस्पताल की स्थापना की। यह एक अनूठा अस्पताल है। यह पूरी तरह से निःशुल्क अस्पताल है। यहां ऑपरेशन और दवाओं सहित सभी प्रकार के उपचार के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आजकल श्री बोरिसागर अहमदाबाद स्थित 'गुजरात विश्वकोष' संस्थान में मातृभाषा - गुजराती के सही उपयोग का शिक्षण देते हैं। वे छात्रों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को लघु कथाओं और कविताओं की व्याख्या और आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी सहायता करते हैं।

श्री बोरिसागर को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे 'मरक मारक' के लिए ज्योतिंद्र दवे कॉमेडी पुरस्कार (1976-1977) (गुजराती साहित्य परिषद); 'मरक मारक' के लिए द्वितीय पुरस्कार, 1977; 'आनंद लोक' के लिए प्रथम पुरस्कार, 1983; गुजरात साहित्य अकादमी, गांधीनगर, गुजरात द्वारा 'एंजियोग्राफी' के लिए प्रथम पुरस्कार, 1997। 'एंजियोग्राफी' के लिए घनश्यामदास सराफ सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार (मारवाड़ी सम्मेलन, मुंबई (1997); धनजी कांजी गांधी स्वर्ण पदक - 2002 (गुजरात साहित्य सभा); 2002 में गुजरात साहित्य अकादमी, गांधीनगर, गुजरात द्वारा 'तिलक काधे त्रिसाथ हो' के लिए प्रथम पुरस्कार और 2004 में 'जीएसटी-के' के लिए प्रथम पुरस्कार; कवि दलपतराम हक्की साहित्य रत्न स्वर्ण पदक - 2011; सच्चिदानंद सम्मान – 2011 (गुजराती साहित्य परिषद);

श्री मीर हाजी कसम, जिन्हें आमतौर पर 'हाजी रामकडू' के नाम से जाना जाता है, गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक महान लोक संगीतकार हैं, जो गुजराती पारंपरिक संगीत के प्रति अपने आजीवन समर्पण और ढोलक वादन में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। छह दशकों से अधिक के कलात्मक सफर में, वे भारत की लोक विरासत के सबसे सम्मानित संरक्षकों में से एक बनकर उभरे हैं। भारत और विदेशों में उनके प्रदर्शनों ने क्षेत्रीय संगीत परंपराओं को जीवित रखने, प्रासंगिक बनाने और नई पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

27 जनवरी 1951 को जन्मे श्री कसम ने महज दस साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा। औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद, उनकी जन्मजात प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लोक कलाकार बना दिया। वर्षों से उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों, गुजराती फिल्म उद्योग की हस्तियों और रेडियो मंचों के साथ मिलकर लोक संगीत की धुनें जनमानस तक पहुंचाई हैं। उनकी अनूठी शैली—जिसमें वे अपने वाद्य यंत्र के साथ एकरूप हो जाते हैं—ने उन्हें स्नेहपूर्वक " रमाकडू " उपनाम दिलाया है।

श्री कसम ने अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कई अन्य देशों में प्रदर्शन करके गुजराती लोक संगीत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हजारों मंच प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया है। युवा संगीतकारों को उनका मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है—जिनमें से कई अब पेशेवर कलाकार हैं—जिसने लोक संगीत की मौखिक परंपराओं को संस्थागत रूप दिया है। वे अपने मानवीय समर्पण के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने गौशालाओं के लिए 35,000 से अधिक परोपकारी कार्यक्रम किए हैं और जूनागढ़ में वंचित परिवारों के विवाहों में सहायता सहित सामाजिक कार्यों के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सत्तर वर्ष की आयु में भी वे बच्चों और उभरते कलाकारों को निःशुल्क लोक संगीत सिखाते रहते हैं, जो कला के माध्यम से निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है।

श्री कसम को गुजरात गौरव पुरस्कार, गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गुजरात लोक कला राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्यमंत्री का मानद पत्र और गुजरात सरकार और प्रमुख संस्थानों द्वारा दिए गए कई सांस्कृतिक पुरस्कारों सहित कई प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। दो दशकों से अधिक समय तक प्राप्त ये पुरस्कार आकस्मिक उपलब्धियों के बजाय निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।

श्री नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला, जिन्हें भारत के 'ऑर्गन मैन' के नाम से जाना जाता है, देश में अंगदान के सबसे समर्पित और प्रभावशाली समर्थकों में से एक हैं। ' डोनेट लाइफ ' के संस्थापक के रूप में, उन्होंने गुजरात और पूरे भारत में मृत शरीर से अंगदान के प्रति जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

19 अप्रैल, 1965 को जन्मे श्री नीलेश मंडलेवाला का इस मानवीय मिशन से जुड़ाव एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके पिता गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें सप्ताह में दो बार डायलिसिस की आवश्यकता होती थी। अपने पिता की शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक संघर्ष को देखकर, उन्होंने महसूस किया कि अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों की गंभीर कमी के कारण भारत भर में हजारों परिवार हर साल इसी तरह की पीड़ा झेलते हैं। व्यक्तिगत पीड़ा को बोझ बने रहने देने के बजाय, उन्होंने इसे जीवन भर के लिए जीवन बचाने और इसी तरह के संकटों का सामना कर रहे परिवारों की सहायता करने के संकल्प में बदल दिया।

वर्ष 2005 में, जब भारत में अंगदान के प्रति जागरूकता अत्यंत सीमित थी और भ्रांतियों, अज्ञानता और भय से घिरी हुई थी, श्री नीलेश मंडलेवाला ने अंगदान जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की। उनका कार्य 2006 में मृत शरीर से गुर्दा दान को बढ़ावा देने से शुरू हुआ और धीरे-धीरे यकृत, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय, आंतों, हाथों, हड्डियों और अन्य ऊतकों के दान के प्रति जागरूकता तक विस्तारित हुआ। उनके समर्पण और विश्वसनीयता ने उन्हें जन स्वास्थ्य जागरूकता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचान दिलाई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 2019 से 2021 तक अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए राज्य सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री नीलेश मंडलेवाला का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2047 तक किसी भी नागरिक की जान अंगों की अनुपलब्धता के कारण न जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक भारत भर में व्यापक यात्राएं की हैं और जागरूकता फैलाई है। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से जुड़ने के लिए रचनात्मक और भावनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने " अंगदान करले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा " गीत की रचना की और " काया - द मिशन ऑफ लाइफ " नामक लघु फिल्म का निर्माण किया, इन दोनों ने ही जन जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंगदान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री नीलेश मंडलेवाला ने मस्तिष्क मृत्यु के बारे में समुदाय को शिक्षित करने और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षणों में परिवारों को अंगदान के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनगिनत शोक संतप्त परिवारों को परामर्श दिया है और अंगदान को सुगम बनाने के लिए डॉक्टरों, अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम किया है। उनके प्रयासों से सूरत को "अंगदाता शहर" के रूप में मान्यता मिली है, जो भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सामाजिक प्रतिरोध, गलत धारणाओं, रसद संबंधी चुनौतियों और बुनियादी ढांचे की सीमाओं का सामना करने के बावजूद, उन्होंने धैर्य, करुणा और असाधारण दृढ़ संकल्प के साथ अपने मिशन को जारी रखा है।

कोविड -19 महामारी के दौरान, श्री नीलेश मंडलेवाला ने अस्पतालों में मस्तिष्क-मृत रोगियों के परिवारों को परामर्श देना जारी रखा और 200 से अधिक अंग और ऊतक दान में योगदान दिया। कुल मिलाकर, उनकी पहलों ने 1371 सफल अंग और ऊतक दान को सुगम बनाने में मदद की है, जिससे 1263 प्राप्तकर्ताओं को नया जीवन और उनके परिवारों को आशा मिली है। " वसुधैव कुटुंबकम " के दर्शन से प्रेरित होकर, उनके कार्य से संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन, रूस, सूडान, यमन और बांग्लादेश सहित कई देशों के रोगियों को लाभ हुआ है।

श्री नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला को गुजरात सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, " गुजरात गरिमा पुरस्कार " सहित 70 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

श्री धर्मिकलाल चुनीलाल पांड्या को गुजरात की प्राचीन मानभट्ट "मान आख्यान" परंपरा के अग्रणी गुरु के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह एक अनूठी मौखिक कथावाचन कला है जिसकी जड़ें मध्यकालीन आख्यान साहित्य में हैं। शास्त्रीय संगीत के साथ महाकाव्यों के लयबद्ध वर्णन, काव्यात्मक अभिव्यक्ति और मान (अंगूठी वाली उंगलियों से बजाया जाने वाला तांबे का बर्तन) के अनूठे प्रयोग के माध्यम से, यह परंपरा सदियों से रामायण, महाभारत, भागवत और पुराणों के साथ-साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संप्रेषित करने का माध्यम रही है।

11 अगस्त 1932 को वडोदरा में जन्मे श्री पांड्या ने अपने पिता चुनीलाल पांड्या से यह कला विरासत में पाई और 1950 के दशक के आरंभ में प्रदर्शन करना शुरू किया। सात दशकों से अधिक समय से, उन्होंने इस लुप्त होती परंपरा को पुनर्जीवित करने और उसे बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित किया है, जब यह विलुप्त होने के कगार पर थी। उन्होंने व्यापक कार्यक्रमों और दीर्घकालिक कहानी सुनाने की श्रृंखलाओं के माध्यम से इस विरासत को गुजरात और पूरे भारत में विभिन्न दर्शकों तक पहुंचाया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन जैसे प्रतिष्ठित स्थल भी शामिल हैं।

श्री पांड्या ने यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नेपाल और थाईलैंड में सांस्कृतिक यात्राओं और आध्यात्मिक व्याख्यानों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनभट्ट परंपरा का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे इस दुर्लभ कला रूप को वैश्विक दर्शकों और भारतीय प्रवासी समुदाय से परिचित कराया जा सका है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ उनके व्यापक रिकॉर्डिंग में हरिवंश पुराण (उत्तर महाभारत से), शिव महापुराण और मध्यकालीन गुजराती कवि प्रेमानंद के सभी चालीस आख्यानों का संपूर्ण पाठ शामिल है। हाल के वर्षों में, उनके परिवार की डिजिटल प्रचार पहलों ने इस परंपरा की पहुंच को और भी बढ़ाया है।

शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करने के अलावा, श्री पांड्या ने जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता जैसे समकालीन सामाजिक विषयों पर नए आख्यान रचे हैं। उन्होंने ' श्री मन आख्यान कला शिक्षण केंद्र ' के माध्यम से प्रशिक्षण को संस्थागत रूप दिया, जहाँ उन्होंने अपने पुत्रों प्रद्युम्न और मयंक पांड्या सहित कई छात्रों का मार्गदर्शन किया, जो आज भी इस कला का प्रदर्शन करते हैं, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।

श्री पांड्या को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिससे वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र मनभट्ट कलाकार बन गए। अन्य सम्मानों में 1980 में जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा कीर्तन केसरी पुरस्कार और मनकला कौशल प्रमाणपत्र; 1980 के दशक में गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी से गौरव पुरस्कार और कई प्रशंसा पुरस्कार; वडोदरा नगर निगम से सम्मान (1984); स्वामीनारायण विचार ट्रस्ट, अमृता संस्थान (मुंबई), गुजरात लोककला केंद्र और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पुरस्कार (गुजरात सरकार, 1994-95) से पुरस्कार; गुजराती साहित्य अकादमी (अमेरिका, 1996) और संन्यास सेवाश्रम (काठमांडू, 2008) से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शामिल हैं। और बाद में संस्कार भारती (वडोदरा, 2009), त्रिवेणी संस्थान (2012), 8वां दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव - संगीत नाटक अकादमी (दिल्ली, 2014), 19वां भारत रंग महोत्सव - राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (दिल्ली, 2017), गुजरात राज्य सरकार (2017), और शाजदा कला केंद्र ट्रस्ट (बेंगलुरु, 2017) से सम्मान और प्रशंसा मिली। .

श्री अरविंद वैद्य एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं जिन्होंने छह दशकों से अधिक समय तक विभिन्न पात्रों को निभाकर गुजराती थिएटर, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

3 मई 1941 को जन्मे श्री वैद्य ने अपनी शिक्षा की शुरुआत 1966 में गुजरात विश्वविद्यालय के एच के आर्ट्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके की। इसके तुरंत बाद, वे उसी संस्थान में व्याख्याता के रूप में लौट आए, जहाँ उन्होंने युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करते हुए 'परित्राण' और 'रायगढ़ झब जग्गे छे' जैसे यादगार गुजराती नाटकों का निर्देशन और अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) में सेवा की, जहाँ उन्होंने निर्माण सहायक के रूप में सार्थक कार्यक्रमों में योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने व्यापक रूप से प्रशंसित श्रृंखला 'भला भूषण भीड़ भरम' में शानदार अभिनय किया।

श्री वैद्य ने अपनी स्वयं की प्रोडक्शन कंपनी ' नाट्य संपदा ' की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने पचहत्तर से अधिक पूर्ण नाटकों का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया। उनकी प्रत्येक रचना में समर्पण की गहरी भावना स्पष्ट रूप से झलकती थी, जिसने उन्हें इस क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई। वर्ष 1993 में मुंबई ने उन्हें अपने कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाने के लिए आमंत्रित किया। बहुभाषी और हमेशा अनुकूलनशील होने के कारण, उन्होंने गुजराती, मराठी और हिंदी रंगमंच में सहजता से काम किया और भोजपुरी फिल्मों में भी कदम रखा। उन्होंने मराठी टेलीविजन धारावाहिक 'हरया नार्या' का निर्देशन किया और अपनी कला को नए क्षेत्रों में विस्तारित किया।

85 वर्ष की आयु में भी श्री वैद्य मंच और स्क्रीन पर सक्रिय हैं—उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने तीन सौ से अधिक नाटकों का निर्देशन या उनमें अभिनय किया है और 100 से अधिक टेलीविजन कार्यक्रमों में अपनी कला का योगदान दिया है। उनके कुछ किरदार आज भी दर्शकों के मन में बसे हुए हैं, जैसे 'नोखी मति ने नोखा मानवी', ' एंटीमी अध्याय', ' परित्राण' और 'अमे बर्फ ना पंखी'; लोकप्रिय शो में 'साराभाई वर्सेस साराभाई', ' बा बहू और बेबी', ' खिचड़ी', ' सास बिना ससुराल', ' लेडीज स्पेशल' और 'अनुपमा' शामिल हैं।

श्री वैद्य को गुजरात सरकार से गौरव पुरस्कार, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सर्वभाषा नाटक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और वे गुजरात संगीत नाटक अकादमी से लगातार सम्मानित होते रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के अनुरूप, VGRC सेंट्रल गुजरात में GI टैग उत्पाद हो सकते हैं प्रदर्शित

▸▸ सेंट्रल गुजरात की GI टैग प्राप्त हस्तशिल्प विरासत को मिलेगा वैश्विक मंच

▸▸ 'वोकल फॉर लोकल' के तहत स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को मिलेगा बढ़ावा

▸▸ अहमदाबाद सोदागरी ब्लॉक प्रिंट, माता नी पछेड़ी और सांखेड़ा फर्नीचर रहेंगे प्रमुख आकर्षण

▸▸ VGRC-मध्य गुजरात, पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक निवेशकों से जोड़ने का बनेगा माध्यम

गांधीनगर, 25 मई : जून के अंतिम सप्ताह में वडोदरा में आयोजित होने वाली सेंट्रल गुजरात क्षेत्र की आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ क्षेत्र की समृद्ध हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगी।

VGRC-मध्य गुजरात में दिखेगी सेंट्रल गुजरात की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत

इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल गुजरात के उन हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किए जाने की संभावना है, जिन्हें भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हो चुका है अथवा जो वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया में हैं। GI टैग किसी उत्पाद की विशिष्ट पहचान, गुणवत्ता और उसके भौगोलिक मूल से जुड़े विशेष महत्व को मान्यता प्रदान करता है। सेंट्रल गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में अहमदाबाद सोदागरी ब्लॉक प्रिंट, माता नी पछेड़ी, पिथोरा पेंटिंग, पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स, अगेट्स ऑफ कैम्बे तथा सांखेड़ा फर्नीचर जैसे अनेक GI टैग प्राप्त उत्पाद शामिल हैं।

सदियों पुरानी परंपराएं बन रही हैं वैश्विक पहचान

अहमदाबाद के जामालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संरक्षित हस्त-मुद्रित वस्त्र कला 'सोदागरी ब्लॉक प्रिंट' को वर्ष 2024 में GI टैग प्राप्त हुआ। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली

आ रही इस परंपरागत कला का अभ्यास मुख्यतः छीपा समुदाय द्वारा किया जाता है। अहमदाबाद और खेड़ा जिलों की प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र कला 'माता नी पछेड़ी' को वर्ष 2023 में GI टैग मिला। देविपूजक समुदाय द्वारा संरक्षित इस कला में कपड़े पर देवी-देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं।

राठवा, भील और भिलाला जनजातियों द्वारा प्रचलित अनुष्ठानिक भित्ति कला 'पिथोरा पेंटिंग' अपने जीवंत रंगों, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और विशिष्ट शैली के लिए जानी जाती है। इस कला को वर्ष 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ तथा यह मुख्यतः छोटाउदेपुर और पंचमहल जिलों में प्रचलित है। इसी प्रकार, गांधीनगर जिले के पेथापुर गांव में पिछले लगभग 300 वर्षों से प्रचलित 'पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स' की हस्तकला को वर्ष 2018 में इसकी विशिष्ट हस्त-नक्काशी तकनीक के लिए GI टैग प्राप्त हुआ।

हड़प्पा सभ्यता से आधुनिक वैश्विक बाजार तक का सफर

आणंद जिले के खंभात (पूर्व में कैम्बे) में तैयार किए जाने वाले रत्न 'अगेट्स ऑफ कैम्बे' को वर्ष 2008 में GI टैग मिला। अगेट शिल्पकला का इतिहास हड़प्पा सभ्यता तक जुड़ा हुआ माना जाता है। वडोदरा जिले के सांखेड़ा कस्बे में खारड़ी-सुथार समुदाय द्वारा निर्मित आकर्षक हस्तनिर्मित 'सांखेड़ा फर्नीचर' को भी वर्ष 2008 में GI टैग प्राप्त हुआ। इस शिल्प में सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर को पारंपरिक रूप से मैरून और सुनहरे रंगों से सजाया जाता है। इसके अलावा, दाहोद बीड वर्क और खंभात काइट जैसे उत्पाद, जिन्होंने GI टैग के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी VGRC (सेंट्रल गुजरात) में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है।

'वोकल फॉर लोकल' से स्थानीय कला को मिलेगा वैश्विक मंच

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन के अनुरूप इन पारंपरिक उत्पादों को 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वडोदरा में आयोजित होने वाली आगामी VGRC सेंट्रल गुजरात के GI टैग प्राप्त उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व संस्करण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुए हैं।

निवेश, नेटवर्किंग और नवाचार का संगम बनेगी आगामी VGRC- मध्य गुजरात

इन रीजनल कॉन्फ्रेंस में एमओयू आदान-प्रदान के अतिरिक्त वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिवर्स बायर-सेलर मीट, व्यापार प्रदर्शनियां तथा सेक्टर-विशिष्ट पवेलियन आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन, MSME के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार, विशेष B2B एवं B2G नेटवर्किंग सत्र, उद्यमी मेला, औद्योगिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण तथा वैश्विक प्रवासी समुदाय के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी समझौते भी प्रमुख आकर्षण रहते हैं।

स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक निवेशकों से जोड़ते हुए तथा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नवाचार को प्रदर्शित करती आगामी VGRC, सेंट्रल गुजरात की संभावनाओं को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रभावी मंच साबित होगी।

क्रूड ऑयल वायदा 479 रुपये फिसला: सोना वायदा में 709 रुपये और चांदी वायदा में 4876 रुपये की वृद्धि

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 24785.38 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 217156.58 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 16161.30 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 241941.95 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 24785.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 217156.58 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2235.79 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16161.30 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 159150 रुपये के भाव पर खूलकर, 159500 रुपये के दिन के उच्च और 158919 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158679 रुपये के पिछले बंद के सामने 709 रुपये या 0.45 फीसदी की बढ़त के साथ 159388 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 473 रुपये या 0.37 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 127676 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 53 रुपये या 0.33 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15969 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 158998 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159259 रुपये और नीचे में 158416 रुपये पर पहुंचकर, 817 रुपये या 0.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 159043 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 159280 रुपये और नीचे में 158420 रुपये पर पहुंचकर, 158235 रुपये के पिछले बंद के सामने 623 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 158858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 276683 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 277245 रुपये और नीचे में 275215 रुपये पर पहुंचकर, 271846 रुपये के पिछले बंद के सामने 4876 रुपये या 1.79 फीसदी की तेजी के संग 276722 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4546 रुपये या 1.65 फीसदी की तेजी के संग 280547 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 4525 रुपये या 1.64 फीसदी की बढ़त के साथ 280564 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 3030.20 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 4.2 रुपये या 0.31 फीसदी की तेजी के संग 1348.9 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मई वायदा 3.75 रुपये या 1.01 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 373.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 55 पैसे या 0.14 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 386.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 40 पैसे या 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 203.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5533.80 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8802 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8880 रुपये और नीचे में 8622 रुपये पर पहुंचकर, 479 रुपये या 5.22 फीसदी घटकर 8689 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 478 रुपये या 5.21 फीसदी लुढ़ककर 8690 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 275.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 276.5 रुपये के दिन के उच्च और 267.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.8 रुपये या 0.65 फीसदी लुढ़ककर 275.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 1.8 रुपये या 0.65 फीसदी लुढ़ककर 275.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 975 रुपये के भाव पर खूलकर, 20 पैसे या 0.02 फीसदी चढ़कर 964 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 8768.16 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7393.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2351.17 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 309.38 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 17.60 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 342.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4326.22 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1173.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.57 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9629 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62602 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20168 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 318730 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47512 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9900 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 25124 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79596 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 16181 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26086 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 208.9 रुपये की गिरावट के साथ 277 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 70 पैसे की नरमी के साथ 2.35 रुपये हुआ।

सोना मई 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 7 रुपये की बढ़त के साथ 98 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 280000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 57 रुपये की बढ़त के साथ 1349 रुपये हुआ। तांबा जून 1450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 74 पैसे के सुधार के साथ 10.8 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे के सुधार के साथ 9 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 56.4 रुपये की बढ़त के साथ 338 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 85 पैसे के सुधार के साथ 8.3 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 134.5 रुपये की गिरावट के साथ 114 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 270000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2551 रुपये की गिरावट के साथ 641.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.68 रुपये की गिरावट के साथ 9.96 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.22 रुपये की गिरावट के साथ 8.5 रुपये हुआ।